प्रचार वाहनों की कमाई एमसीएफ को नहीं, ठेकेदारों की जेब में जा रही

तीन विज्ञापन एजेंसियों पर 8 करोड़ बकाया, वाहन से अलग कर रहे है कमाई

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबादः नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) के लिए काम कर रही विज्ञापन एजेंसियां दोनों हाथों से एमसीएफ को लूट रही है। मजदूर मोर्चा के पिछले अंक में आपने यूनीपोल और जेंट्री लगाने की आड़ में की जा रही वसूली और नगर निगम को उसका बकाया पैसा न देने की खबर पढ़ी थी। अब पढ़िए कि इन एजेंसियों द्वारा जिले में घुमाए जा रहे विज्ञापन वाहनों से किस तरह कमाई की जा रही है और उसका एक अंश भी एमसीएफ में जमा नहीं कराया जा रहा। अदालत की तरफ से आदेश है कि चलते-फिरते वाहनों पर इस तरह प्रचार नहीं किया जा सकता। क्योंकि इससे किसी का ध्यान भंग होने पर हादसे का खतरा रहता है।

तीन एजेंसियां, 20 वाहन

शहर में तीन विज्ञापन एजेंसियों स्क्वायर आउटडोर सर्विस, श्याम एंटरप्राइजेज और ग्लोबल एडवरटाइजिंग इंडिया के पास एमसीएफ का ठेका है। ये कंपनियां एनआईटी, ओल्ड फरीदाबाद और बल्लभगढ़ जोन में यूनीपोल, जेंट्री लगाने और अन्य तरह के होर्डिंग और फेलेक्सी लगाने का काम करती हैं। लेकिन इसकी आड़ में इन एजेंसियों के करीब 20 वाहन भी विज्ञापन करते घूमते हैं। इन विज्ञापन वाहनों को शहर की प्राइम लोकेशन पर देर तक खड़ा रखा जाता है और आते-जाते लोग बिना इन्हें देखे बढ़ ही नहीं पाते। आमतौर पर बिल्डर अपने नए प्रोजेक्ट का प्रचार या बड़ी-बड़ी एफएमसीजी कंपनियां अपना प्रचार इन वाहनों के जरिए कराती हैं। ये वाहन कभी तो बड़े वाले ट्रक और कभी बस के आकार में होते हैं। एमसीएफ ने नियम बना रखा है कि ऐसा प्रचार वाहन चलाने पर विज्ञापन एजेंसी को प्रति वाहन एक लाख रुपये जमा कराने पड़ते हैं। लेकिन इन तीनों एजेंसियों ने अपने प्रचार वाहनों के बारे में किसी तरह की जानकारी एमसीएफ को नहीं दे रखी है।

मुफ्त का दफ्तर

तीनों एजेसियां चूंकि एमसीएफ के लिए काम करती हैं तो इन्होंने नगर निगम से एक साइट मांग रखी है, जहां ये अपने होर्डिंग, जेंट्री, यूनीपोल वगैरह रख सकें। एमसीएफ ने इन तीनों एजेंसियों को सेक्टर 21सी में पानी की टंकी के परिसर में जगह दे रखी है। लेकिन विज्ञापन एजेंसियां अपने प्रचार वाहन लाकर इस जगह पर अवैध रूप से खड़ा कर देती हैं। हर समय छह-सात प्रचार वाहन एमसीएफ की इस जगह पर खड़े रहते हैं। एमसीएफ चाहे तो इनसे इसका किराया वसूल सकता है लेकिन एमसीएफ जब अवैध रूप से चल रहे प्रचार वाहनों को लेकर इन एजेंसियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है तो प्रचार वाहन खड़ा करने पर इनका क्या उखाड़ पाएगा।

पानी की टोंटी लगाकर शुरुआत

तीनों विज्ञापन एजेंसियां इतनी चालाक हैं कि वे अपने प्रचार वाहनों को सीधे प्रचार के लिए नहीं उतारती हैं। वे सबसे पहले इन वाहनों में पानी की टोंटी लगाती हैं ताकि जनसेवा का ढोंग किया जा सके। इसके बाद वाहनों में लगी पानी की इन टोंटियों का उद्घाटन किसी मंत्री, भाजपा नेता या पार्षद से कराया जाता है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर तक ऐसे वाहनों पर लगी पानी की टोंटियों का उद्घाटन कर चुके हैं। ऐसे वाहनों की टोंटियों पर करीब एक हफ्ते या दस दिन तक कोई प्रचार नहीं होता है। इनका प्रचार पोर्टलों, अखबारों या फेसबुक लाइव पर होता है कि फलां नेता ने पानी की टंकी के वाहन का उद्घाटन किया। इस घटनाक्रम के कुछ दिन बाद उस वाहन पर बड़े-बड़े प्रचार होर्डिंग या फ्लेक्सी लगा दिए जाते हैं। उसके बाद वह प्रचार वाहन शहर में घूमने लगता है।

इसी तरह ये विज्ञापन एजेंसियां पुलिस स्टेशनों पर पुलिस के होर्डिंग के साथ प्राइवेट संस्थाओं के विज्ञापन, अस्पतालों के बाहर विज्ञापन, तमाम बड़े सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों के बाहर लगे विज्ञापनों के जरिए भी कमाई कर रही हैं लेकिन इनका पैसा भी एमसीएफ के खाते में नहीं पहुंच पा रहा है। शहर के बड़े-बड़े मॉल्स के बाहर लगे विज्ञापनों से इन्हें कमाई हो रही है लेकिन उसका पैसा एमसीएफ के खाते में नहीं जा रहा है।

नेताओं का संरक्षण

तीनों विज्ञापन एजेंसियां सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं, विधायकों, मंत्रियों, पार्षदों का विज्ञापन मुफ्त में कर रही हैं। इसलिए उन्हें एमसीएफ के नियम-कानून का कोई डर नहीं है। तीनों जोन में विज्ञापन कंपनियों पर एमसीएफ का करीब 8 करोड़ रुपये बकाया है। लेकिन वे एमसीएफ को भुगतान नहीं कर रही हैं। हाल ही में नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल ने तीनों एजेंसियों को एक महीने का समय दिया था लेकिन एजेंसियों ने कमिश्नर के नोटिस को भी कूड़ेदान में फेंक दिया। किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया। वजह यही है कि अगर कुछ होगा तो नेताजी देख लेंगे। यही वजह है कि शहर में नेताजी के होर्डिंग की भरमार है, जिसमें वो फरीदाबाद की जनता की तरफ से जबरदस्ती प्रधानमंत्री मोदी को मुफ्त वैक्सीन के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। सौ रुपये लीटर का पेट्रोल डालकर गाड़ी चला रहे लोग इन होर्डिंग के नीचे से गुजरते समय भद्दी-भद्दी गालियां देकर गुजरते हैं।

तीनों विज्ञापन एजेंसियों ने अगर एमसीएफ के 8 करोड़ रुपये डकार लिए और उसके प्रचार वाहन भी इसी तरह अवैध रूप से घूमते रहे तो एमसीएफ समझौते की शर्तों के हिसाब से इन पर बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं कर सकता। वह ज्यादा से ज्यादा इन्हें ब्लैकलिस्ट कर सकता है। लेकिन यही कंपनियां नया नाम रखकर फिर से एमसीएफ का ठेका उठा लेंगी। पहले भी ऐसा हो चुका है। प्रतिबंधित विज्ञापन एजेंसी ने एमसीएफ का ठेका नए नाम से उठा लिया।

गुड़गांव के जज की टिप्पणी से देश के लोग कुछ सीखें

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

गुड़गांव की एक अदालत का हालिया फैसला, जिसने नफरत फैलाने वाले भाषण देने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इन्कार कर दिया, भारत में जहरीली साम्प्रदायिक भाषा बोलने वालों पर कुछ हद तक अंकुश लगा सकता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मोहम्मद सगीर ने हाल ही में 19 साल के रामभक्त गोपाल शर्मा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा, "धर्म या जाति के आधार पर अभद्र भाषा आजकल फैशन बन गई है।" गुड़गांव के पटौदी में एक सभा में शर्मा पर आरोप लगा था कि उन्होंने मुस्लिम लड़कियों के अपहरण और हत्या का आह्वान किया था। उसके वीडियो भी सामने आए थे।

"पटौदी में इस युवक की टिप्पणी के फुटेज से अदालत भी स्तब्ध है। ऐसी घटनाओं से निपटने में पुलिस भी बेबस नजर आती है। इस प्रकार की कार्रवाइयाँ अनिवार्य रूप से हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बाधित कर रही हैं और भारतीय संविधान की भावना को नष्ट कर रही हैं,"मजिस्ट्रेट सगीर ने अपने 11-पृष्ठ के आदेश में लिखा, "आरोपी व्यक्ति द्वारा किए गए कथित अपराध की प्रकृति बहुत गंभीर हैं और कि इस समय, अभियुक्त के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाज के शांतिपूर्ण सांप्रदायिक सद्भाव के अधिकार के खिलाफ प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है"।

संयोग से, रामभक्त गोपाल शर्मा पर फरवरी 2020 में नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पास सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करने का भी आरोप है, जिसमें एक छात्र घायल हो गया। बताया जाता है कि शर्मा ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते समय "मैं देता हूं आजादी" (मैं तुम्हें आजादी दूंगा) कहा था, जबकि दिल्ली पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी मुश्किल से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी थी और तमाशा देख रही थी। उस समय यह नाबालिग था और आसानी से कोर्ट से छूट गया था। रॉयटर्स के फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी ने वह फोटो खींचा था, जो अब ऐतिहासिक हो चुका है। दुनिया के कई अन्य हिस्सों की तरह, पिछले कुछ वर्षों में भारत में भी जहरीले और भड़काने वाले बयान की घटनाएं कहीं अधिक आम हो गई हैं, राजनेताओं, विशेष रूप से दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों ने खुले तौर पर इसका इस्तेमाल हिन्दू - मुस्लिम समुदायों को आपस में बांटने और हिंदू वोट हासिल करने के लिए किया है। इस्लामोफोबिया और सांप्रदायिक दुश्मनी बढ़ाने में इस पार्टी का विशेष योगदान है।

'रामभक्त' गोपाल शर्मा की जामिया वाली फोटो

पिछले साल जनवरी 2020 में, नई दिल्ली में दो प्रमुख स्थानों - शाहीन बाग और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सीएए विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। "फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों पर एक जांच कमेटी की रिपोर्ट" के अनुसार, 23 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। इसके तुरंत बाद भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने जाफराबाद के पास एक छोटा भाषण दिया जिसमें सीएए विरोधियों को हटाने का आह्वान किया गया था। न केवल कपिल मिश्रा ने बल्कि मौके पर मौजूद भाजपा समर्थकों के सदस्य भी "हर हर मोदी" और "मोदी जी, काट दो मुल्लों को जैसे नारे लगाते हुए उस इलाके में हिंसा करने लगे। वे नारे लगा रहे थे - "आज तुम्हें आजादी देंगे।"

इसी तरह उस समय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी वहां एक रैली में सीएए विरोधियों पर निशाना साधते हुए जहरीला नारा लगाया। अनुराग ठाकुर ने कहा-"देश के गद्दारों को, गोली मारो सालो को"।

दिल्ली हाई कोर्ट के वकील मोहसिन कुरैशी कहते हैं "जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से सार्वजनिक सभाओं में जहरीली भाषा के भाषणों में भारी वृद्धि हुई है। और इसके पीछे एक मुख्य कारण यह है कि भाजपा में चुने गए अधिकांश नेताओं की कोई न कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है। एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार, मोदी कैबिनेट में 78 मंत्रियों में से 42 प्रतिशत के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो चुकी है, जिनमें से चार पर हत्या के प्रयास से संबंधित मामले हैं।

क्या कोई बड़ा कांड होने के बाद 1-2 चौक की अराजकता खत्म होगी

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबादः एनआईटी 1-2 चौक की विशेषता और इसकी उपयोगिता किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से छिपी नहीं है। पुलिस कमिश्नर से लेकर डीसी तक जानते हैं कि 1-2 एनआईटी चौक शहर का बिजनेस हब है, इसके बावजूद यहां पर अव्यवस्था का जो आलम है, वो किसी से छिपा नहीं है। इस चौराहे के पास कम से कम एक दर्जन बैंकों और फाइनैंस कंपनियों के दफ्तर हैं। लेकिन न तो खराब सीसीटीवी और न ही खराब रेड लाइट को ठीक किया जा रहा है। इस संबंध में समाजसेवी और भाजपा नेता सुरेंद्र गेरा का कहना है कि इस चौराहे की रेड लाइट तो पिछले एक साल से खराब पड़ी है। उन्होंने इस संबंध में कई बार अधिकारियों को पत्र लिखा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

गेरा का कहना है कि इस चौक की समस्या यहीं पर सीमित नहीं है। इस चौराहे पर दोनों तरफ रेहड़ियों की भरमार है। दोनों तरफ आटो वाले हर वक्त सवारियों के लिए खड़े रहते हैं। इसका नतीजा यह निकल रहा है कि शहर का यह पूरा चौराहा ही अराजकता का शिकार हो गया है। यहां पूरा दिन हजारों गाड़ियां निकलती हैं। लेकिन ट्रैफिक अव्यवस्था होने की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। उनका कहना है कि आसपास के बैंक या फाइनैंस कंपनी में कोई अपराध हो गया तो पुलिस के वाहनों को पार करने में ही समय लग जाएगा। आग लगने की घटना होने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तक यहां फंस सकती हैं। गेरा ने कहा कि दरअसल, बीके चौक से लेकर हार्डवेयर चौक तक ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। कारोबार और आम जनता के मद्देनजर यह रोड शहर की सबसे महत्वपूर्ण रोड है, लेकिन अव्यवस्था की शिकार है।